

प्रेषक,

पी. सी. शर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास

देहरादून : दिनांक 27 मई, 2011

विषय— मानसून अवधि में अतिवृष्टि, बाढ़, त्वरित बाढ़ एवं नदियों के जल स्तर बढ़ने के फलस्वरूप विशेष सतर्कता बरतने के संबन्ध में।

महोदय,

राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण मानसून अवधि में होने वाली भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़, त्वरित बाढ़, बाढ़ फटना, अतिवृष्टि एवं नदियों के जल स्तर बढ़ने के कारण अत्यधिक जन-धन की हानि एवं सार्वजनिक क्षेत्र की परिसम्पत्तियों की क्षति की संभावना के दृष्टिगत संभावित आपदाओं हेतु पूर्व तैयारी एवं राहत व बचाव कार्यों हेतु विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

उक्त के संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मानसून अवधि में आपदा के बेहतर प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण उपायों हेतु आपदा पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर तैयारी एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1. जनपदों में प्राथमिकता के अनुसार भूस्खलन, बाढ़ आदि से सम्बन्धित संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण कर उक्त स्थानों के निकटतम आपदा राहत संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसे स्थानों से नियमित सूचनायें प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए।
2. मानसून अवधि में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों तथा बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों को 24X7 के आधार पर नियमित रूप से संचालित किया जाए। इस हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमानुसार पर्याप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित कर ली जाए।
3. जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग से समन्वय स्थापित कर विभागीय नोडल अधिकारी नामित करा लिये जाए। नामित नोडल अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की दैवी आपदा की स्थिति में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को अपने विभाग से संबन्धित सूचना उपलब्ध करायी जायेगी, तथा सूचना का संकलन, विश्लेषण कार्ययोजना की तैयारी के साथ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों द्वारा संकलित सूचना तत्काल राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त विभागों के नोडल अधिकारियों के नाम/पदनाम/दूरभाष (कार्यालय/आवास) तथा मोबाइल नम्बर जनपद

21

आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध करा दिये जाए।

4. 7 डेस्क सिस्टम से सम्बन्धित नामित नोडल अधिकारियों से भी अनवरत समन्वय रखा जाए, जिससे किसी आपदा के समय सुव्यवस्थित राहत/बचाव एवं प्रतिवादन किया जा सके। मानसून सत्र में इन अधिकारियों की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह अवश्य की जाए। नोडल अधिकारी अपने पास अपने से सम्बन्धित संसाधनों की सूची (Resource Inventory) हर समय उपलब्ध रहनी चाहिए।
5. सेंट्रल वाटर कमीशन, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सिंचाई विभाग एवं मौसम विभाग तथा अन्य विभागों/संस्थाओं की मदद से ऐसे क्षेत्रों में नदियों के बहाव/व्यवहार की सतत जानकारी रखी जाए तथा विभिन्न स्रोतों से सूचनायें संकलित कराकर Early Warning System स्थापित करते हुए ऐसे क्षेत्रों को त्वरित बाढ़ आने से पूर्व ही खाली कराकर जन-धन की सुरक्षा के समुचित उपाय सुनिश्चित किये जाएं ताकि बचाव कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न हो।
6. नदियों के जल स्तर की भी निरन्तर समीक्षा करते रहे, नदी तटों पर स्थित आबादी क्षेत्रों एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण तथा शासन को संभावित आपदा की प्रत्येक स्थिति से समय पूर्व तैयारी व कृत कार्यवाही से कृपया अवगत कराते रहें।
7. केन्द्रीय जल आयोग, बाढ़ प्रबन्धन संगठन भारत सरकार द्वारा भी मानसून अवधि में बाढ़ एवं अन्य दैवी आपदाओं की घटनाओं की दैनिक एवं साप्ताहिक रिपोर्ट हेतु प्रारूप निर्धारित किये गये हैं, जो जनपदों को पूर्व ही प्रेषित किये जा चुके हैं। अतः निर्धारित प्रारूप पर दैवी आपदा की घटित घटनाओं की सूचनायें शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाए ताकि उक्त सूचनायें समय पर भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य में स्थित प्रमुख नदियों के जलस्तर एवं बाढ़ की स्थिति की जानकारी हेतु अपने स्तर पर समुचित सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर संबंधित कार्यों हेतु राज्य हित में एकरूपता स्थापित करने का प्रयास किया जाए।
8. बाढ़ के दृष्टिगत विशेष रूप से प्रभावित होने वाले जनपद हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल तथा देहरादून में बाढ़ सुरक्षा से संबंधित तैयारी की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली जाए। ऐसे प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर जनजागरुकता व खोज एवं बचाव से संबंधित जानकारी दे दी जाए।
9. दैवी आपदा के समय त्वरित बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन तथा बाढ़ आने से प्रशासनिक मशीनरी को Response Time कम मिल पाता है, तथा संभावित क्षति रोकने के लिए प्रभावी (Preventive) निरोधात्मक कार्यवाही समय से पूर्व नहीं हो पाती है। अकस्मात होने वाली घटनाओं के कारण अग्रिम चेतावनी देना व समय से पूर्व क्षेत्र को खाली न करा पाना आपदा का एक मुख्य कारण बन जाता है। अतः ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों का सामना करने व समय से पूर्व चेतावनी देते हुए क्षेत्रों को खाली कराने का कार्य कराना जन-धन की सुरक्षा हेतु परम आवश्यक है। जनपद स्तर पर इस हेतु त्वरित कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए।

10. दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त तात्कालिक प्रकृति की विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत/ पुर्ननिर्माण कार्य एवं प्रभावितों को राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मद में धनराशि पूर्व ही जिलाधिकारियों को आवंटित की जा चुकी है/की जा रही है। अतः सी.आर.एफ. मानकों के अनुसार क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/ पुर्ननिर्माण एवं प्रभावितों में राहत सहायता वितरण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।
11. जिन क्षेत्रों में बाढ़ तथा त्वरित बाढ़ (Flash Floods) आने की सम्भावना हो, में खनन कार्य रोकने तथा ऐसे संभावित खतरनाक क्षेत्रों में मजदूरों इत्यादि को असुरक्षित स्थानों से आपदा आने से पूर्व ही हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए।
12. समस्त जनपदों में मौसम विभाग द्वारा स्थापित Rain Gauge का रख रखाव एवं दैनिक वर्षा की सूचना फ़ैक्स/ रेडियोंग्राम द्वारा प्रतिदिन भेजी जानी सुनिश्चित की जाए।
13. जनपदों में बरसाती नालों तथा नदियों की अतिक्रमित भूमि पर निर्मित भवनों को यथाआवश्यकता अतिशीघ्र खाली करा दिया जाए तथा जनजागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचार प्रसार किया जाए।
14. बाढ़ इत्यादि दैवी आपदाओं के समय सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एकजुटता के साथ निपटा जाए तथा दैवी आपदा की स्थिति में राहत शिविरों, चिकित्सा सुविधाओं एवं खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था पूर्व तैयारी के अंतर्गत सुनिश्चित करा ली जाए।
15. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र 24 घंटे खुला रहता है। अतः किसी भी प्रकार की दैवी आपदा की सूचना तत्काल ई-मेल seoc.dmmc@gmail.com व दूरभाष संख्या- 1070, 0135-2710334 तथा फ़ैक्स संख्या-0135-2710335 पर उपलब्ध करा दी जाए।
16. पूर्व में राज्य में जिन स्थानों पर भूस्खलन तथा त्वरित बाढ़ से संबंधित आपदा की घटनायें हुई हैं, उन स्थानों पर विशेष ध्यान देना तथा भूस्खलन प्रभावित राजमार्ग का वैकल्पिक मार्ग को वन विभाग के समन्वय से तय करना जैसे जनपद बागेश्वर का कपकोट, जनपद पिथौरागढ़ का धारचूला, जनपद रुद्रप्रयाग, जनपद उत्तरकाशी के मोरी, नैटवाड़, चमोली, बूढ़ाकेदार आदि संवेदनशील स्थान।
17. समस्त जनपदों में मुख्य तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपदा से पूर्व तथा आपदा के बाद फैलने वाली बिमारियों की रोकथाम हेतु बनायी गई योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
18. जनपद ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर राहत शिविरों के लिये चिन्हित भवनों की स्थिति तथा अतिरिक्त राहत शिविरों की व्यवस्था की जाए।

21

19. लोक निर्माण विभाग तथा सीमा सड़क संगठन के उपकरणों, विशेष रूप में Dozer, Earth moving Equipment, Cranes आदि की उपलब्धता तथा संवेदनशील स्थानों पर इनकी उपलब्धता की स्थिति की जानकारी उपलब्ध करायी जाए।
20. दैवी आपदा की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, गैर सरकारी संगठन तथा निजी संस्थानों के जनपद में उपलब्ध रोगी वाहन, मोबाइल हैल्थ वाहनों यथा- EMRI 108 का सहयोग लिया जाए।
21. जनपद तथा मण्डल स्तर पर आपदा के दौरान सेना, आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी., पी. ए.सी. तथा अन्य पैरामिलिट्री दलों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना।
22. बचाव व राहत कार्यों में सहायतार्थ, राज्य स्तर पर दो कम्पनी क्रमशः श्रीनगर व अल्मोड़ा में State Disaster Response Force (SDRF) राज्य आपदा प्रतिवादन दल भी तैनात किये गये हैं, जिनका आवश्यकतानुसार सहयोग राहत एवं बचाव कार्यों हेतु लिया जाय।
23. राष्ट्रीय स्तर पर National Disaster Response Force, NDRF की स्थापना की गई है। जिसकी भानू एवं ग्रेटर नोयडा स्थित 02 बटालियनों से जरूरत पड़ने पर सम्पर्क किया जा सकता है।
24. केन्द्रीय जलायोग द्वारा नदियों के जल प्रवाह/जलस्तर एवं दैनिक वर्षा से संबंधित सूचनाएँ नियमित रूप से आपदा प्रबन्धन विभाग, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को नियमित रूप से उपलब्ध करवायी जाए तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा तैयार की जाने वाली दैनिक/ नियमित आख्याओं में वर्षा एवं जलप्रवाह संबंधित सूचनाओं को समावेश अवश्य किया जाए।
25. मौसम विभाग द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर पर स्थापित आपातकालीन परिचालन केन्द्र को नियमित रूप से मौसम संबंधित सूचनायें प्रेषित की जानी सुनिश्चित की जाए।
26. टिहरी जल विद्युत विकास निगम (टी.एच.डी.सी.) व अन्य संबंधित विभागों द्वारा टिहरी जलाशय एवं जल प्रवाह की स्थिति की सूचना जनपद एवं राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को नियमित रूप से प्रेषित की जानी सुनिश्चित करते हुए निरन्तर अनुश्रवण एवं सुरक्षा व बचाव हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।
27. मानसून अवधि में विषम परिस्थितियों को छोड़कर आपदा कार्य से जुड़े एवं समय-समय पर प्रशिक्षण प्राप्त समस्त विभागों के अतिआवश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश प्रदान न किया जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(पी. सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव

21